



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2164]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2009/अग्राहायण 30, 1931

No. 2164]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2009/AGRAHAYANA 30, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3251(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 308(अ), तारीख 10 मार्च, 2006 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लक्षद्वीप तटीय जोन प्राधिकरण का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है;

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्षद्वीप तटीय जोन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात प्राधिकरण का गठन करती है। इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. प्रशासक, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र                    | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र | —सदस्य   |
| 3. उप वन संरक्षक, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र             | —सदस्य   |
| 4. अधीक्षण इंजीनियर, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग          | —सदस्य   |

5. डॉ. के. वी. थॉमस, वैज्ञानिक, सेंटर फार अर्थ साईंस स्टडीज, तिरुवनन्तपुरम —सदस्य

6. डॉ. एम. वाफर, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा —सदस्य

7. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, भूतल परिवहन मंत्रालय, पोर्ट ब्लेयर या उनका प्रतिनिधि —सदस्य

8. निदेशक मत्स्य, लक्षद्वीप प्रशासन —सदस्य

9. सदस्य सचिव, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति । —सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजेडएम्पी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन

के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तककि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु उप-खण्ड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

- III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेट क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XII. प्राधिकरण का मुख्यालय कावारति में स्थित होगा।

XIII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटारा जाएगा।

[फा. सं. 12-3/2005-आईए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 21st December, 2009

**S.O. 3251(E).**—Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O 308(E), dated the 10th March, 2006, the Central Government reconstituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority, for period of three years and the term of the said Authority has been expired;

And Whereas, the Central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this order, namely :—

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Administrator,                      | —Chairman |
| Union Territory of Lakshadweep         |           |
| 2. Secretary,                          | —Member   |
| Department of Environment and Forests, |           |
| Union Territory of Lakshadweep         |           |
| 3. Deputy Conservator of Forests,      | —Member   |
| Union Territory of Lakshadweep         |           |
| 4. Superintending Engineer,            | —Member   |
| Lakshadweep Public Works Department    |           |
| 5. Dr. K.V Thomas, Scientist,          | —Member   |
| Centre for Earth Science Studies       |           |
| Thiruvananthapuram                     |           |
| 6. Dr. M. Wafer, Scientist,            | —Member   |
| National Institute of Oceanography,    |           |
| Goa                                    |           |

7. Chief Engineer and Administrator, —Member  
Andaman Lakshadweep Harbour Works,  
Ministry of Surface Transport,  
Port Blair or his representative

8. Director of Fisheries, —Member  
Lakshadweep Administration

9. Member-Secretary, —Member  
Lakshadweep Pollution Control Secretary  
Committee.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Lakshadweep, namely :—

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Lakshadweep Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made there under or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made there under or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under clauses (a) and (b) may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under Section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);

(iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii);

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Andhra Pradesh, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti.

XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-3/2005-1A-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'